

nt>

Title: Need to increase the minimum support price of agricultural produce.

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष जी, हमारे कृषि प्रधान देश में किसानों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। खेती अब फायदे का सौदा न होकर घाटे का सौदा हो गयी है। ऋण के जाल में फंसेकर आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। अकेले आंध्र प्रदेश में पिछले 6 महीनों में करीब 1800 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। किसानों को जब तक उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक उनकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। उनको उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की व्यवस्था की है। पिछले एक साल में खेती के उत्पादन में काम आने वाली चीजों, बीज, खाद, कीटनाशक और डीजल के दाम लगभग 40 प्रतिशत बढ़े हैं लेकिन इस साल सरकार ने जिस समर्थन मूल्य की घोषणा की है उसमें गेहूं में 10 रुपये और चने में 25 रुपये बढ़ाए हैं। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। जिस प्रकार से 40 प्रतिशत लागत बढ़ी है और एक प्रतिशत समर्थन मूल्य बढ़ा है यह किसानों के साथ न्याय नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गेहूं में कम से कम 40 रुपये और चने में 50 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की जानी चाहिए। आज किसानों के लिए यह वृद्धि बहुत आवश्यक है। एनडीए की सरकार ने जो कृषि फसल आय बीमा योजना 20 जिलों में लागू की थी, उसका विस्तार पूरे देश में किया जाए। बीमे की इकाई आप तहसील को मानते हैं, जिसके कारण किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। तहसील के स्थान पर गांव या किसान को इकाई माना जाए। यह प्रार्थना मैं आपके माध्यम से सरकार से करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री एन.एन. कृणदास - अनुपस्थित। श्री खारबेल स्वाई।